



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 24 अप्रैल, 2023

बैशाख 4, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग—2

संख्या 513/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी०सी० 213-उ०प्र०अधि०-१-२०१७-आदेश (271)-२०२३
लखनऊ, 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प०आ०—३४७

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के सम्बन्ध में नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में तत्त्वानी प्रविष्टियों में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलम्ब फीस की रकम को एतद्वारा अधित्यक्त करती है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अध्यधीन पच्चीस रुपए प्रति दिन।
2	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पाँच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अध्यधीन पचास रुपए प्रति दिन।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 या 2021–22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के सम्बन्ध में संदेय विलम्ब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

2—यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 513 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.213-U.P.Act-1-2017-Order (271)-2023, dated April 24, 2023 :

No. 513 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.213-U.P.Act-1-2017-Order (271)-2023

Dated Lucknow, April 24, 2023

IN exercise of the powers conferred by Section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in Column (3) of the table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the table below, who fails to furnish the return by the due date, namely :–

TABLE

Serial Number	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 percent of turnover in the State or Union territory.
2	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the relevant financial year.	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 percent of turnover in the State or Union Territory.

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 31st day of March, 2023.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यूपी0—ए0पी0 262 राजपत्र—2023—(764)—599 प्रतियां (कम्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यूपी0—ए0पी0 3 सा0 राज्य कर—2023—(765)—1000 प्रतियां (कम्यूटर/टी0/ऑफसेट)।